

इन्द्रकांत ग्रिपाठी के परिजनों से मिलने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधायक दल नेता आराधना मिश्रा 'मोना' गिरफ्तार, देर शाम रिहा

● हत्या, डकैती, बलाकार ग्रष्टाचार और कोरोना ने प्रदेश में जाए आयान स्थापित किये: अजय कुमार लल्लू ● डीएम एसपी अपराध की नईरी घला रहे हैं, अफसर लेते हैं फिरौती योगीराज में: अजय कुमार लल्लू ● सरिधान की हत्या हो रही है योगीराज में, देषपूर्ण तरीके से बाधित की जा रही है राजनीतिक प्रक्रिया: आराधना मिश्रा मोना ● प्रदेश में जंगलराज अपने घरम पर, महिला हिंसा और अपराधों का हब बना उत्तर प्रदेश: आराधना मिश्रा मोना ● योगीराज में कानून व्यवस्था वेटिलेटर पर, अपराध और कोरोना में मची है होड़: सोहेल अख्तर अंसारी

लखनऊ, संचाददाता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कोटी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, हत्या, बंदोधनों के साथ बलाकार और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार पर संघर्ष निशाना साधते हुए कहा कि योगी से प्रदेश की बाग़ेर और अब सभाली नहीं जा रही है, बहत होगा कि वो इसीका देकर जनता के घाव पर मरहम खेलने का काम करें, प्रदेश जीवन जानता उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि +क्या अपराधी, क्या अधिकारी सब जनता को लूटने में व्यस्त हैं। यह जंगलराज की पराक्रांत ही है कि पुलिस द्वारा मनवाल हो चुके हैं। पुलिस का इक्काल रोज़ रक्त-रंजित होता है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि +क्या अपराधी, क्या अधिकारी सब जनता को लूटने में व्यस्त हैं। यह जंगलराज की विल्कुल धूस हो गयी है। हत्या, बेहत होगा कि वो इसीका देकर जनता के घाव पर मरहम खेलने का काम करें, प्रदेश जीवन जानता उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल धूस हो गयी है। हत्या,

अचौलो से



नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज बमरौली में हिन्दी परिवारों का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया

प्रयागराज। अंतुल दीक्षित, कार्यपालक निदेशक व प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्ञलित करके इस कार्यक्रम का सुभारम्भ किया। शरणगात्र श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (संचार) एवं विक्रम कपूर, महाप्रबंधक (वा.या.प्र.) भी इस अवसर पर उत्कर्ष साथ शामिल हुए। अंतुल दीक्षित ने इस अवसर पर यू.मंत्री, भारत सरकार का काम सदैर संप्रेषित करने के साथ-साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यालयीन काम-काज में साधारण व सहज हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। उहोंने यह भी कहा कि इस कार्यालय द्वारा 95 प्रतिशत से अधिक हिन्दी पत्राचार इस तथा को परिषुट करता है कि इस संस्थान के तकनीकी स्तर के होते हुए भी अधिकारी कार्यक्रम के हिन्दी में काम-काज को प्राथमिकता देते हैं। कार्यालय में

चंदन बने विधान सभा अध्यक्ष



मण्डलायुक्त ने 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की

प्रयागराज। मण्डलायुक्त आरोहन समाचार के मंदेन्जर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने संगठन को मण्डलीय देने के लिए युवाओं पर भरोसा जाताया है। मेजा के मैवैया निवासी युवा नेता चंदन सिंह यादव को मेजा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। मनोनयन के बाद चंदन सिंह ने पांच अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव एवं यादव का आधार जाताया, साथ ही कहा कि पार्टी के प्रति अपने कर्तव्यों का निवारण पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ करता रहा।

प्रयागराज। मण्डलायुक्त आरोहन समाजवादी पार्टी ने संगठन को मण्डलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की गठन हेतु उसीस्थित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। उहोंने सम्बोधित अधिकारियों को मण्डलायुक्त सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया। श्रेष्ठ जीवा अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को मण्डलायुक्त निवारण समिति का गठन किये जाने सम्बंधी कार्यवाली करने के लिए निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डलायुक्त खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के अन्तर्गत खेलों को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं व दिव्यांजनों को खेलों में प्रतिभागिता हेतु आकर्षित किया जाये। उन्होंने अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल लेने के लिए बजाए रखा है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने जाने के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्तरांग ने अपनी पूर्णता के लिए जीवनकारी प्रारंभिक निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने स्कूलों को खेलों के लिए चिन्हित करते हुए अन्तर्गत जिला प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने तथा स्कूलों में खेल के अवस्थापनाओं को भी चिन्हित करने को कहा। उन्होंने स्मार्ट सीटी के अन्तर्गत अपेन जिम स्थापित कराये जाने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। साथ ही नेहरू यादव के जो केन्द्र सक्रिय नहीं हैं, उहें सम्बोधित अधिकारियों की विवादाता विधान सभा के अवधिकारी ने उत्त

ਰਾਫ਼ੇਲ: ਏਕ ਨਜ਼ਾਰ ਇਥਰ ਮੀ

भारत-चौन के बीच चल रहा जबरदस्त तना तनी के बीच प्रांस निर्मित बहुचर्चित एवं विवादित युद्धक विमान श्राफेलश् गत 10 सितम्बर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इस अवसर पर अंबाला छावनी स्थित वायुसेना स्टेशन पर एक समारोह आयोजित हुआ जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी प्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पालें व सेना व वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले जब राफेल ने 29 जुलाई 20 को भारत की धरती पर अंबाला एयर फेर्स्ट स्टेशन के रनवे पर अपनी सबसे पहली लैंडिंग की थी उस समय भी इन युद्धक विमानों का जोरदार स्वागत किया गया था। राफेल को वॉटर सेल्यूट देते हुए दोनों ओर से फयर ब्रिगेड के स्प्रे के बीच से निकाला गया था। पूजा पाठ व राफेल को बुरी नजर से बचाने का सिलसिला तो प्रांस से लेकर अंबाला तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदी में बल्कि उन्हीं के पावन हाथों से होता आया है। नींबू-मिर्च व नजर उतारने के सभी शउपायश् भी किये जा चुके हैं। रक्षा मंत्री ने हैपी लैंडिंग इन अंबाला का सन्देश देकर राफेल का स्वागत किया था। गैरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा प्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा लगभग 59,000 करोड़ रुपये में किया गया है। इन्हीं 36 राफेल फाइटर विमानों में से मात्र 5 विमानों का पहला बैच प्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़कर संयुक्त अरब अमीरात होता हुआ अंबाला पहुंचा है और उन्हीं 5 विमानों की शान में 29 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक के यह सभी समारोह आयोजित होते रहे हैं। खबर है कि दिसंबर 2021 तक संभवतरू सभी 36 राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। 29 जुलाई को जिस दिन 5 राफेल की आमद हो रही थी उस दिन का मीडिया कवरेज

तथा अम्बाला वायुसेना स्टेशन के आसपास के सुरक्षा प्रबंध देखने लायक थे। अम्बाला वायु सेना क्षेत्र में प्रवेश निषेध होने के बावजूद मीडिया बता व दिखा रहा था कि किस समय 5 राफेल की टुकड़ी ने भारतीय आकाश में प्रवेश किया और आकाश में ही भारतीय वायु सेना के दो सुखोई फ़ाइटर विमानों ने उनकी अगवानी की। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्ध पोते आईएनएस कोलकाता द्वारा भी भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर राफेल का स्वागत किया गया। 29 जुलाई को मीडिया के लगातार प्रसारण ने विशेषकर अंबाला में कुछ ऐसा माहौल बना दिया था कि हजारों लोग तेज धूप के बावजूद अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर वायु सेना के इस नए मेहमान के दर्शन करने को बेचौन दिखाई दिए। कुछ स्थानीय अखबारों ने उस दिन अंबाला में आज दीवालीश जैसे शीर्षक लगाकर राफेल के आने की

खबर प्रकाशित की थी। 29 जुलाई को राफेल की सुरक्षा के दृष्टिगत अंबाला जिला प्रशासन द्वारा एयर एर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर परिक्षेत्र में ड्रेन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रशासन हाई एलट पर था तथा राफेल लैंडिंग के दौरान छोटों से फेनेग्राफी करना व लोगों का जमावड़ा लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। पक्षी उड़ाने व पतंगबाजी करने तक पर रोक थी। जाहिर है यह सभी एहतियाती उपाय इसीलिये किये जा रहे थे ताकि बेशकीमती राफेल की सुरक्षा में कोई चूक या कमी न रह जाने पाए। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पूर्व भी अंबाला वायु सेना स्टेशन मिग-21 व जगुआर जैसे युद्धक विमानों का केंद्र रहा है। देश के पश्चिम क्षेत्र की महत्वपूर्ण निगरानी केंद्र होने के कारण यहां दशकों से मिग-21 व जगुआर प्रायरूप अपनी नियमित उड़ानें भरते रहते हैं। कम से कम ऊंचाई पर भी

उड़ने को क्षमता रखने वाले इन विमानों की सुरक्षित उड़ान के मद्देनजर ही इस हवाई क्षेत्र के आसपास के इलाके में तीन मणिला इमारत बनाए जाने पर कानूनन रोक है। परन्तु इसी शहर में मोबाइल टावर्स की भरमार जरूर है। राफेल की भारी क्लीमत और चीन से चल रहे वर्तमान तनावपूर्ण हालात को देखते हुए न केवल समस्त भारतवासियों बल्कि सभी सरकारी व गैर सरकारी विभाग के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे राफेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस दिशा में अपना हार संभव योगदान भी दें। पिछले दिनों मैंने रात के समय अग्नाता के आसपास विशेषकर शहरी क्षेत्र का भ्रमण इसी मकसद से किया ताकि देख सकूँ कि राफेल की आमद पर जश्न मनाने वाला देश आखिर राफेल की सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर है। मैंने पाया कि 50 पुट से लेकर 200 पुट तक की ऊँचाई वाले अधिकांश मोबाइल

वारसे के शोष का सकत दर्ने वाला ताल लाईट बुझी हुई है। इन्होंने बल्कि बोएसएनएल व रेलवे टार्मसे माइक्रोवेव टार्मसे जो कि नगभग 350 से लेकर 500 पुट वट की ऊँचाई रखते हैं उनमें भी नई टार्मसे के शीर्ष पर आवश्यक व्य से जलने वाली संकेत रूपी ताल बत्ती बुझी हुई थी। मिग हो या नगुआर या अब भारतीय वायु सेना नया शामिल हुआ राफेल, जरूरत डूने पर या अपनी नियमित उड़ान समय भी कभी-कभी बहद कम ऊँचाई पर उड़ते हैं। राफेल की सुरक्षा प्रति वायुसेना के अधिकारियों की चिंता का अदाजा इस बात से नयाया जा सकता है कि गत 10 संतंबर को राफेल के औपचारिक व्य से वायुसेना के बड़े में विधिवत शामिल होने से पूर्व ही भारतीय वायु सेना के निरीक्षण और सुरक्षा वहनिदेशक, एयर मार्शल मानवेंद्र संह ने, हरियाणा की मुख्य सचिव, शनी आनंद अरोड़ा को एक आधिकारिक पत्र लिखकर अबाला एयर फेर्स्ट स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में कच्चा निपटाने के लिए त्वरित उपाय करने का अनुरोध किया है। ऐसा पत्र कच्चे के चलते पक्षी इक होने व इनके उड़ने के कारण राफेल लड़ाकू विमान की सुरक्षा को होने वाले संभावित खतरे के दृष्टिगत लिखा गया है। गौरतलब है कि अंबाला वायुसेना क्षेत्र में पक्षियों की संख्या अधिक होने कारण टकराव होने से इन बेशकीमती विमानों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वायु सेना ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग से भी मांग की है कि कम से कम अंबाला एयरफील्ड के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में पतंगों व बड़े पक्षियों की गतिविधि को कम करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना (एसडब्ल्यूएम) को तत्काल कार्यान्वित किया जाए। वायु क्षेत्र से उपयुक्त दूरी पर उपयुक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) सबधा प्लाट तत्काल स्थापित किया जाए। इन्होंने बल्कि वायु सेना स्टेशन के आसपास कबूल प्रजनन गतिविधि को निषिद्ध व नियन्त्रित करने के लिए भी प्रशासन से कहा गया है। जाहिर है कि राफेल के शुभागमन मात्र से ही राफेल की जरूरत नहीं पूरी होने वाली बल्कि इसके रखरखाव की सबसे अहम जरूरत अर्थात् इसकी पूर्ण सुरक्षा तथा इसके लिए निर्बाध हवाई रास्ता उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों को आपसी तालमेल से यथाशीघ्र इसकी सुरक्षा संबंधी सभी उपाय करने चाहिए। सभी ऊंचे टार्मसे की लाल बत्ती रात के समय तत्काल जलनी चाहिए और हवाई क्षेत्र के आसपास से कूड़े के निपटान का काम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना (एसडब्ल्यूएम) की स्थापना आदि जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

सम्पादकाय

लोकतांत्रिक बहस के पथधर थे अग्निवेश

हिंदौ माध्यमों को हिंदौ को परवाह नहीं

The image is a vibrant collage of Hindi text. It features numerous words and characters in different colors—red, orange, yellow, and black—arranged in a non-linear, overlapping fashion. The text is in a variety of fonts, some appearing as large, bold letters and others as smaller, more delicate script. In the center of the collage, the words 'हिंदी दिवस' (Hindi Diwas) are prominently displayed in a large, bold, black font. The background is a light, neutral color, which makes the colorful text stand out.

जसम सरकारा कामकाज किया जाता है, लेकिन आज भी गौकरशाही की भाषा अंग्रेजी है। फेरोना काल में अपने देखा होगा के हिंदी भाषी राज्यों में भी गंगेजी में निकलते हैं। अखबार हिंदी नां न छापें, तो जनता की समझ में ही आये कि निर्देश क्या है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश तो खासा चर्चा में रहा था, जिसमें ऐसी अंग्रेजी भाषा का स्तेमाल किया गया था, जो किसी नो समझ में नहीं आयी थी। उसको समझाने के लिए मंत्रालय को पृथकरण जारी करना पड़ा था। बॉलीवुड को ही लें, जिसमें माजल हैं क काइ हदा म बात करता नाता है, लेकिन आज भी गौकरशाही की भाषा अंग्रेजी है। फेरोना काल में आपने देखा होगा के हिंदी भाषी राज्यों में भी गंगेजी में निकलते हैं। अखबार हिंदी नां न छापें, तो जनता की समझ में ही आये कि निर्देश क्या है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश तो खासा चर्चा में रहा था, जिसमें ऐसी अंग्रेजी भाषा का स्तेमाल किया गया था, जो किसी नो समझ में नहीं आयी थी। उसको समझाने के लिए मंत्रालय को पृथकरण जारी करना पड़ा था। बॉलीवुड को ही लें, जिसमें माजल कवल अंग्रेजी म बात करता था। हम ठहरे ठेठ हिंदी भाषी और छोटे जिले से आया व्यक्ति, जिसका अंग्रेजी में हाथ तंग था। मैंने पाया कि केवल हिंदी भाषी होने के कारण मुझे कमरा किये पर नहीं मिल पा रहा था। बाद में यूपी के एक मित्तल साहब की कृपा हुई, जिन्होंने हमें पनाह दी। यह सही है कि भारत विविधता भरा देश है और इसमें अनेक भाषाएँ बोलियां बोली जाती हैं और हरेक का अपना महत्व है, लेकिन पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली एक भाषा का होना बेहद जरूरी है। यह बात दीगर है कि राजनीतिक कारणों से नेताओं को यह पसंद नहीं है।

महाराष्ट्र में सत्तापक्ष का आ बल मुझा मार

मुम्बई में शिवसेना व मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे के खिलाफ अभियान चलाना इस अर्थ में महांग पड़ा है कि बुहन्मुर्बई युनिसिपल कारपोरेशन बीएमसी) ने उनके कार्यालय को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया। जब तक कंगना के बकील हाईकोर्ट से स्टे लाते, बीएमसी ने तपतरापूर्वक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली। अलबता, इसकी सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ने इस बाबत उससे जवाब मांगा है। मामले को व्यापक परिप्रेक्ष में देखें तो सवाल है क्या संविधान किसी सरकार को अपनी पसन्द-नापसन्द के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान पहुंचाने की स्वतंत्रता या अधिकार देता है? और जवाब है-नहीं, संविधान सबके साथ समान व्यवहार की बात कहता है। इस मामले को लेकर उद्घव सरकार की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार की यह अपत्ति व्यावहारिक राजनीतिक नेता की ही ज्यादा दिखती है कि बीएमसी की यह कार्रवाई विरोधियों के बढ़यन्त्र में खुद जा फंसने जैसी है। यकीनन, संविधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई मुख्यमंत्री, उसकी सरकार या पार्टी किसी के प्रति नाराज या खुश होकर देरे से एक वर्ष तक सारी तो राजनात जा भी कराये और यह मामला राजनीति से कितना गहरे तक जुड़ा है, इसे यों समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी, जो भाजपा के उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे जुड़े बीएमसी अधिकारियों को समन भेजकर बुलाने का प्रयत्न किया है। यह तब है, जब माना जाता है कि संविधानिक प्रमुख होने के बावजूद जब तक निर्वाचित सरकार कार्यरत है, राज्यपाल स्वयं व्यवस्था संचालित करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना संविधानिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के अनुसार राज्यपाल जैसे ही राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है, उसके परामर्शों के अनुसार कार्य करने का ही अधिकारी रह जाता है। मुख्यमंत्री के किसी कार्य या व्यवहार से असंतुष्ट होने पर भी उसे अधिकारियों को तलब करने या बुलाने का अधिकार नहीं होता। तब तक, जब तक मुख्यमंत्री को हटाकर राष्ट्रपति शासन न लगा दिया जाए। फिल्हाल, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछे भी कंगना मामले में राज्यपाल की दिलचस्पी का हाल यह है कि वे अनुचित रूप से अधिकारियों को नाम देते थे असाधा तो असाधी तो बल्कि एक पक्ष के लाभ-हानि से भी सम्बद्ध है। राज्यपाल का यह कदम ठीक वैसे ही है, जैसे उन्होंने भाजपा नेता फड़णवीस को रातों-रात पिछ से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। बाद में फड़णवीस ने स्वयं ही यह मानकर इस्तीफ दे दिया था कि न उह विधानसभा में बहुमत प्राप्त, न ही वे उसे सिद्ध कर सकते हैं। बेहतर होता कि राज्यपाल समझते कि आदर्श स्थिति यह है कि राज्यपाल का विवेक किसी भी स्थिति में वैयक्तिक लाभ-हानि या स्वार्यों से जुड़ा हुआ न दिखे। जहां तक बीएमसी के अधिकारियों का सम्बन्ध है, उसे अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति भी सजग और सचेत रहना, साथ ही किसी प्रकार के भेदभाव या पार्टीबन्दी से विलग रहना चाहिए। क्योंकि वे उस पार्टी की अनुचित अपेक्षाएं पूरी करने के अधिकारी नहीं हैं, जिसका बीएमसी में बहुमत हो। कंगना रनौत के कार्यालय के निर्माण में कोई अनियमितता हुई हो तो उन्हें उस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए अपने विवेक के अधिकार का दुरुपयोग करने का नहीं। ऐसा कोई भी दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए अशुभ व अनुचित है और उसे जारी करने की विवादित विधियां विधानसभा के बाहर जैसे मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी नेता भी उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे और उसे चुनौती दे रहे हों। पवार न सिर्फ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो हैं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री और कई बार केन्द्रीय मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना या उद्घव ठाकरे की राजनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ण पवार की पार्टी के विवादियों के बगैर संभव नहीं थी। पवार उद्घव ठाकरे से बेहतर जानते हैं कि पद और समर्थन किसी भी सरकार को अनुचित निर्णय लेने और राजनीतिक बदले के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देते। इतना ही नहीं, जिसे अलोकतांत्रिक या अनुचित कहा जाता हो, ऐसे कदम उठाये जाने के आरोप प्रायरू सत्ता के विपरीत ही जाते हैं। कंगना के कार्यालय का निर्माण अवैध था और बीएमसी ने उसकी स्वीकृति नहीं दी थी, तब भी उसे ऐसे दिन ढाहने का कोई तुक नहीं था, सत्ता दल से तनाती और मीडिया हाइप के बीच जिस दिन वे मुम्बई आ रही थीं। क्योंकि बीएमसी अवैध निर्माणों को ढाहने का कोई अधियान नहीं चला रही थी। जिस परामर्श में 20 विधायिका ने देशी जाल में फँस गई है। उसने जिस तरह अहंकार प्रदर्शन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, उसके मद्देनजर उच्च न्यायालय का निर्णय भी उसके पक्ष में आने की उम्मीद नहीं है। न्यायालय किसी भी दृष्टि से इस जल्दबाजी में किये गये इस ध्वस्तीकरण का समर्थन नहीं कर सकता और इस बाबत उसकी टिप्पणियां विरोधी राजनीतिक नेताओं को कहीं ज्यादा लाभकारी दिखेंगी। शरद पवार की सलाह भी उद्घव सरकार को अवश्यक करार देकर ध्वस्तीकरण के अदेश पर अमल किया जा चुका है। लेकिन न्यायालय को अभी भी अपने विवेक के अनुसार उचित-अनुचित का निर्णय करने का अधिकार है और राज्य से लेकर केन्द्र सरकार तक उसके निर्णयों को मानने के लिए विधिवत मजबूर भी हैं। इस सिलसिले में कोई भी विपरीत आदेश शिवसेना और उद्घव सरकार की परेशानियां बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। वैसे भी जल्दबाजी में किये गये इस ध्वस्त को उचित नहीं ठहराया जा सकता। शरद पवार ठीक ही कह रहे हैं कि इस ध्वस्तीकरण से कंगना को गैरजस्ती प्रचार मिला और वे खुद को पीड़ित बताकर जन सहानुभूति अर्जित करने में सफल रहीं। ऐसी सहानुभूति हमेशा सरकारों व सत्ता दलों के खिलाफ ही जाती है। जब इससे जुड़ा प्रश्न सीधे आन्दोलन से जुड़ जाए, तब तो और अभी यह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से राजनीतिक लाभ के लिए ही उपयोग के लिए वित्त लाता है।

